

पत्र क्रमांक 2 (12) 79-2 जी० एस० III

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
चण्डीगढ़।

सेवा में

1. हरियाणा सरकार के सभी विभागाध्यक्ष
2. आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल।
3. सभी उपायुक्त हरियाणा।

दिनांक, चण्डीगढ़

5.9.1980

विषय—

निलम्बित कर्मचारियों के केसों का शीघ्र निपटान करने बारे हिदायत-18 मास से अधिक अवधि से निलम्बित कर्मचारियों की सूची।

महोदय,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आप का ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 2 (12) 79-2 जी० एस० III दिनांक 24.8.80 की ओर दिलाऊँ जिस द्वारा 18 मास से अधिक निलम्बित सरकारी कर्मचारियों की मासिक सूचियाँ इस विभाग को भेजी जानी होती है। प्राप्त सूचियाँ से जो त्रुटियाँ सरकार के नोटिस में आई हैं वे निम्नलिखित हैं:—

1. प्रायः विभाग निर्धारित तिथि तक अपेक्षित सूचियाँ नहीं भेजते। ऐसी स्थिति में रिपोर्ट भेजने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। आपसे अनुरोध है कि यह मासिक रिपोर्ट निर्धारित तिथि तक अवश्य भेजी जाए।
2. Statement I (Casses pending in Courts) इस सूची के सभी कालम ठीक ढंग से नहीं भरे जाते। कालम नं० 3 में एफ० आई० आर० की तिथि और पुलिस स्टेशन के बारे कालम 5 में चालान की तिथि तथा कालम 7 में केस की वर्तमान स्थिति (अर्थात् कि मामला गवाही की स्टेज पर हैं, निर्णय की स्टेज पर है आदि) प्रायः नहीं बताई जाती। अनुदेश क्रमांक 33/13/79-1 जी० एस० I, दिनांक 16.4.79 द्वारा यह भी अपेक्षित है कि न्यायालयों में लम्बित मामलों, के सम्बंध में एक वर्ष से अधिक निलम्बित कर्मचारियों के बारे मंत्री परिषद की अनुमति प्राप्त की जाए। अतः निवेदन है कि स्टेटमेंट-1 के कालम 8 में इस बारे भी पूर्ण स्थिति दर्शायी जाए। संशोधित स्टेटमेंट 1 की प्रति संलग्न है।
3. Statement-II (Casses pending with departments) के कालम 7 में बहुधा विभागों द्वारा date of starting of enquiry के बारे सूचना नहीं दी जाती।
4. Statement-III (Casses pending with Police) के कालम 9 में केस की नवीनतम स्थिति तथा देरी के कारण नहीं बताए जाते और न ही nature of allegation बारे कालम 4 में सूचना दी जाती है।
2. आप से अनुरोध है कि अपेक्षित सूचियाँ भेजते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि उपर्युक्त त्रुटियाँ न

रहने पाएँ।

संयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक-एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:—

1. वित्तायुक्त राजस्व तथा
2. हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव।

संयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. वित्तायुक्त राजस्व तथा,
2. हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव।